

प्रेषक,

टीकम सिंह पंवार,
अपर सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक,
उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण, उत्तराखण्ड,
उद्यान भवन चौबटिया-रानीखेत।

उद्यान एवं रेशम अनुभाग-1

देहरादून: दिनांक- 18 फरवरी, 2016

विषय:- वित्तीय वर्ष 2015-16 के अन्तर्गत अनुदान संख्या-29-00-आयोजनेत्तर पक्ष की योजनाओं हेतु प्रथम अनुपूरक अनुदान के माध्यम से प्राविधानित धनराशि की स्वीकृति के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्रांक-526/एक-1(1)/2015-16, दिनांक-05 नवम्बर, 2015 एवं वित्त अनुभाग-1, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या-400/XXVII(1)/2015, दिनांक-01 अप्रैल, 2015 के अनुक्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि चालू वित्तीय वर्ष 2015-16 में विभागीय अनुदान संख्या-29 के आयोजनेत्तर पक्ष के अन्तर्गत प्रथम अनुपूरक माँग के माध्यम से प्राविधानित धनराशि लेखाशीर्षक 2401-फसल कृषि कर्म-00-आयोजनेत्तर-119-बागवानी और सब्जियों की फसलें-03-औद्योगिक विकास-0301-अधिष्ठान हेतु रु० 15500 हजार, 0302-राजभवन के उद्यानों का सुदृढीकरण हेतु रु० 2174 हजार, 0304-सचिवालय परिसर का सौन्दर्यीकरण हेतु रु० 382 हजार समग्र रूप से कुल धनराशि रु० 18056 हजार (रु० एक करोड़ अस्सी लाख छप्पन हजार मात्र) की धनराशि संलग्न विवरण/कम्प्यूटर आई०डी० के अनुसार आपके निर्वर्तन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल निम्नांकित शर्तों/प्रतिबन्धों के अन्तर्गत सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

- 1- इस धनराशि का व्यय केवल चालू कार्यों के लिये ही किया जायेगा।
- 2- धनराशि का व्यय केवल उन्हीं मदों में किया जाय, जिनके लिए यह स्वीकृति निर्गत की जा रही है।
- 3- बजट प्राविधान से अधिक व्यय किसी भी दशा में न किया जाय और न ही पुनर्विनियोग व अन्य माध्यम से अतिरिक्त बजट की प्रत्याशा में कोई व्यभार/दायित्व सृजित किया जायेगा।
- 4- धनराशि का व्यय करते समय वित्त अनुभाग-1, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या-400/XXVII(1)/2015, दिनांक-01 अप्रैल, 2015 एवं समय-समय पर निर्गत शासनादेशों में निहित दिशा-निर्देशों का अनुपालन किया जाय।
- 5- किसी भी शासकीय व्यय हेतु प्रक्योरमेन्ट रूल्स, 2008, भण्डार कय प्रक्रिया (स्टोर्स पर्चेस रूल्स) वित्तीय नियम संग्रह खण्ड-1, वित्तीय अधिकारों का प्रतिनिष्पादन नियम संग्रह खण्ड-5 आय व्यय सम्बन्धी नियम शासनादेशों आदि का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
- 6- व्यय की सूचना निर्धारित बजट मैनुअल के प्रपत्रानुसार प्रत्येक माह की 20 तारीख तक वित्त विभाग को अवश्य उपलब्ध करायी जाय तथा इन मदों के अन्तर्गत आहरण एवं व्यय मासिक आधार पर किश्तों में वास्तविक व्यय आवश्यकता के अनुरूप ही किया जायेगा।

- स्वीकृत की जा रही धनराशि विभागीय नियंत्रणाधीन सम्बन्धित आहरण वितरण अधिकारियों को तात्कालिकता से अवमुक्त कर दी जाय, ताकि फील्ड स्तर पर बजट उपलब्ध न होने की स्थिति उत्पन्न न हो।
- 8- राज्य सरकार द्वारा जो नयी योजनायें स्वीकृत की गयी हैं, उन योजनाओं में अवमुक्त धनराशि का व्यय शासन द्वारा योजनाओं के मानक स्वीकृत होने के उपरान्त एवं मानकों के अनुसार ही किया जायेगा। मानक निर्धारित न होने की दशा कमें किसी भी प्रकार का कोई व्यय किसी भी मद में नहीं किया जाय। अनुमोदित मानकों में परिवर्तन का अधिकार विभाग को नहीं होगा। मानकों के अनुसार योजनाओं का क्रियान्वयन न होने की दशा में सम्बन्धित अधिकारी का उत्तरदायित्व होगा।
- 9- मजदूरी तथा व्यावसायिक सेवाओं के लिये भुगतान मदों के अन्तर्गत आउटसोर्सिंग से कार्मिकों की संख्या सम्बन्धित इकाई में समक्ष स्तर के स्वीकृत परन्तु रिक्त पदों की अधिकतम सीमा अन्तर्गत अथवा वित्त विभाग की पूर्व सहमति से स्वीकृत सीमा, इनमें जो भी कम हो, के अन्तर्गत ही रहेगी।
- 10- योजनागत पक्ष में चालू योजनाओं एवं चालू निर्माण कार्यों के लिए (आयोजनेत्तर पक्ष सहित) आय-व्यय के अन्तर्गत प्राविधानित धनराशि आहरण वितरण अधिकारियों को एकमुश्त जारी न करते हुए सर्वप्रथम सम्बन्धित अधिकारियों से पूर्व निर्गत धनराशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र प्राप्त किया जाय। उपयोगिता प्रमाण पत्र प्राप्त होने के उपरान्त सन्तुष्टि की दशा में वित्त विभाग के शासनादेश दिनांक-17-11-2015 में निहित व्यवस्थानुसार अग्रेत्तर धनराशि अवमुक्त की जाय, उक्ता कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।
- 11- इस सम्बन्ध में होने वाला उद्यान विभाग के अनुदान संख्या-29 लेखाशीर्षक 2401-फसल कृषि कर्म-00-आयोजनेत्तर-119-बागवानी और सब्जियों की फसलें-03-औद्यानिक विकास-0301-अधिष्ठान, 0303-राजभवन के उद्यानों का सुदृढीकरण, 0304-सचिवालय परिसर का सौन्दर्यीकरण में अंकित सुसंगत प्राथमिक इकाईयों के नामे डाला जायेगा।
- 12- यह आदेश पत्रावली में प्राप्त वित्त विभाग उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।
- संलग्नक:-यथोपरि।**

भवदीय,

(टीकम सिंह पंवार)
अपर सचिव।

संख्या-1853/XVI(1)/15/7(5)/2015, तददिनांकित।

प्रतिलिपि:-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- महालेखाकार, उत्तराखण्ड, ओबराँय मोटर्स बिल्डिंग माजरा, देहरादून।
- 2- आयुक्त गढ़वाल मण्डल पौड़ी/कुमायूँ मण्डल नैनीताल।
- 3- सम्बन्धित वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
- 4- वित्त अनुभाग-4, उत्तराखण्ड शासन।
- 5- बजट राजकीय नियोजन एवं संसाधन निदेशालय, उत्तराखण्ड।
- 6- राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र, सचिवालय परिसर, देहरादून।
- 7- गार्ड फाईल।

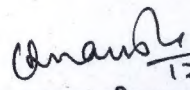
आज्ञा से
(विकास कुमार श्रीवास्तव)
अनु सचिव।

शासनादेश संख्या-1855/XVI(1)/15/7(5)/2015, दिनांक- 18 फरवरी, 2016 का संलग्नक

(धनराशि हजार रू0 में)

क0 सं0	योजना का नाम	अनुपूरक माँग से प्राविधान वित्तीय वर्ष 2015-16	अवमुक्त होने वाली धनराशि
	2401-फसल कृषि कर्म 00-आयोजनेत्तर 119-बागवानी और सब्जियों की फसलें 03-औद्यानिक विकास		
1-	0301-अधिष्ठान		
	16-व्यावसायिक तथा विशेष सेवाओं के लिए भुगतान	15000	15000
	44-प्रशिक्षण व्यय	500	500
	योग-0301	15500	15500
2-	0302-राजभवन के उद्यानों का अनुरक्षण (भारित)		
	26-मशीने और सज्जा/उपकरण और संयंत्र	564	564
	31-सामग्री और सम्पूर्ति	1410	1410
	42-अन्य व्यय	200	200
	योग-0302	2174	2174
3-	0304-सचिवालय परिसर का सौन्दर्यीकरण		
	31-सामग्री और सम्पूर्ति	382	382
	योग-0304	382	382
	महा योग:-	18056	18056

(रू0 एक करोड़ अस्सी लाख छप्पन हजार मात्र)


(विकास कुमार श्रीवास्तव)
अनु सचिव।